प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 31 मई, 1977 तक 11,89,63,994·83 रु० शेष था ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक लेखा वर्ष (जुलाई से जून तक) के अन्त में उक्त कोष में शेष इस प्रकार था :—

1973–74	87,51,977.57 रु०
1974–75	89,87,145.00 रु०
1975–76	10,77,59,940·99रु०

इस कोष के मुख्य स्रोत लोगों द्वारा ऐच्छिक रूप से दिये गये अंशदान तथा बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल अंशदान इस प्रकार है :—

1973–74	22,19,153.82 रु०
1974–75	32,12,853.72 रु०
1975–76	11,61,01,768.55 रु०

सदन की मेज पर उन अंशदाताओं के नाम तथा उनके अंशदान के विवरण रख दिए गए है जिन्होंने बड़ी मात्रा मे अंशदान दिये हैं [**विवरण ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** L.T. 472 77]

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से इस प्रकार धन खर्च किये गये :—

1973–74	20,95,243.44 रु०
1974–75	36,06,207.84 रु०
1975–76	2,00,12,810.00 रु०

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, खान दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से यह धन बांटा गया । सहायता कार्य में लगे कुछ संगठनों को अनुदान दिये गये। ऐसे कुछ व्यक्तियों को भी अनुदान दिये गये जिनके सामने वित्तीय संकट था, जिसका मुख्य संबंध उनकी शिक्षा तथा चिकित्सा की समस्याओं से था, जिससे कि वे अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को पार करने में समर्थ हो सकें । एक दो परोपकारी कोषों में भी अनुदान दिये गए ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री जी की जानकारी में यह है कि 1975–76 में श्री आर एन को जो हैड हैं आर० ए० डब्ल्यू० के उनके परामर्श से उन्हीं के परिवार के लोगों को बड़ी धनराशि दी गई ? क्या इस की केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस पर केन्द्रीय सरकार कोई आयोग या इसी सदन और राज्य सभा के पांच पांच या सात सात सदस्यों की कोई जांच कमेटी बिठा कर इस की जांच कराएंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी जांच बिठाने की जरूरत नहीं है । मैं जांच कर लूंगा ।

श्री बलबीर सिंह : जांच करने के बाद अगर यह पाया गया कि यह धनराशि ठीक ढंग से खर्च नहीं की गई, गलत ढंग से की गई है तो कोई एकशन भी आप उनके खिलाफ लेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : जो जरूरी काम होगा वह करेंगे ?

Shortage of Houses for Scheduled Castes in Delhi

*146. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government or any of its agencies have made a survey of

shortage of houses for Scheduled Caste families in Delhi;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) how many dwelling units have been constructed for Scheduled Caste families in Delhi in the last three years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). While no special survey as such has been conducted, the following two schemes have been in operation during the last three years:

(i) *Grant of financial assistance by the Delhi Administration.*—3492 Scheduled Caste families have been given financial assistance.

(ii) *Allotment of flats by way of reservation by the Delhi Development Authority.*—3165 flats have been allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes families.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि दिल्ली में करीब दो लाख डवैलिंग यूनिट्स की जरूरत है और उन में से अधिकांश शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिन के पास मकान नहीं है। पहली सरकार ने जो पैसा दिया वह बहुत कम था और नाममात्र को ही दिया था। क्या मंत्री महोदय दुबारा सर्वे कराएंगे कि दिल्ली में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कितने मकानों की जरूरत है ? सर्वे करा करके आगे इस साल या अगले साल उनको ज्यादा मकान मिलें क्या इस प्रकार की कोई योजना आप बनाएंगे ?

श्री चरण सिंह : सवाल तो आसानी से हो गया लेकिन जवाब मुश्किल है। आपने यह जो कहा कि दो लाख मकानों की जरूरत है यह मैं नहीं मनाता हूं। इसका कारण यह है कि 1971 में 40 लाख 65 हजार 700 जनसंख्या थी। उस में से शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या थी 6 लाख 35 हजार 700। पांच आदमियों के पीछे एक डवैलिंग यूनिट चाहिए। इस तरह से एक लाख 26 हजार चाहियें। अब आबादी बढ़ गई है। डेढ़ लाख हो गई होगी। डेढ़ लाख में से एक लाख तो निकल गए। वे आज आखिर सड़कों पर तो नहीं रह रहे हैं। पचास हजार की आवश्यकता है। अब क्या स्कीम बनेगी वह इसके ऊपर निर्भर करता है कि माननीय सदन कितना रुपया हमें देगा। गुप्त जी इसमें मदद करेंगे ऐसा मैं मानता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय बताएंगे कि 3492 परिवारों को जो रुपया दिया है उनको कुल कितना दिया है और बजट में आपने इस चीज के लिए कितना रुपया इस साल मांगा है ताकि हम उतना दे सकें ?

श्री चरण सिंह : आपने तीन साल का सवाल किया है, 1974–75, 1975–76 और 1976–77 का। तो 1974–75 में 12 लाख रु०, 1975–76 में 18 लाख रु० और 1976–77 में 10 लाख और अब मौजूदा साल चल रहा है इस में इस के लिए रखा गया है 24 लाख 50 हजार रु०। तो इस प्रकार 64 लाख 50 हजार रु० बैठता है।

SHRI P. K. KODIYAN: May I know from the hon. Minister, whether apart from giving houses to the Scheduled Caste people in Delhi, there is any proposal to provide them developed land so that with the money received from Government out of the grant they can construct their own houses?

SHRI CHARAN SINGH: I would say that there are two kinds of schemes: under one scheme—provided the man concerned can produce Rs. 500 of his own—the Development Authority will provide Rs. 1500 in three instalments and there is another condition attached to it and that is the plot should be of 60 sq. yards. Then alone this sum of Rs. 1500 will be given to him.

श्री समर गुह : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है बल्कि और भी बड़े बड़े शहरों की है जहां लाखों की तादाद में आदमी मकान-हीन हैं जो बेचारे रास्ते में रहते हैं और रात भी रास्ते में बिताते हैं। यह लोग अधिकतर शैड्यूल्ड कास्ट के हैं। तो क्या आप सोचेंगे कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि में जहां होमलैस लोग हैं उनको रीहेबिलिटेट करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

MR. SPEAKER: The question will be wide. You may answer it. But the other questions will suffer. If you raise questions about Bombay and Calcutta, the other Members will raise questions about Hyderabad and Bangalore.

SHRI SAMAR GUHA: I have used the word etc.

MR. SPEAKER: Members stand to suffer. The other questions will go unanswered. If you ask questions about Bombay, Calcutta, Allahabad and Lucknow, somebody may ask questions about Gwalior. You will lose the time of the question hour.

New Projects for Power Generation

*150. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any new projects for power generation have been installed in various parts of the country; and

(b) if so, places where they have been located?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). Yes, Sir. Many new projects have already been commissioned in various parts of the country during the first 3 years of the Fifth Five Year Plan. The total Hydro and Thermal capacity installed in 1974-75, 1975-76 and 1976-77 is 5236.4 MW. The units have been installed in various parts of the country *viz.* Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Orissa, West Bengal, Assam, Bihar, Tripura, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Punjab, Haryana, Delhi, Damodar Valley Corporation area and Madhya Pradesh.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the hon. Minister has stated in his reply certain new projects which have already been commissioned in various parts of the country. I would like to know whether he has taken note of the Fifth Plan outplay which is about Rs. 7000 crore which is meant for generation of hydro and thermal capacity for these projects? But before that, there is a point regarding stagnation of industrial growth in the country. They are not only lagging beyond these needs for industrialisation but there are other facilities which are required on which the growth of various States including Maharashtra, West Bengal—except Kerala—and Karnataka depends. The power shortage is very acute. It is mainly because of lack of understanding and coordination between the national policy evolved and the functioning of the various State Electricity Boards. May I know whether the Minister has taken note of the need to have certain national involvement, to adopt a national policy, by creating new projects in various parts of our country. During the tenure of his office in the last two months....

MR. SPEAKER: Ask your question.